



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 272      राँची, बुधवार,      20 वैशाख, 1938 (श०)  
10 मई, 2017 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----  
संकल्प  
9 मार्च, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-720/जेल, दिनांक 21 मार्च, 2016 एवं पत्रांक- 1719/जेल, दिनांक 16 जून, 2016
  2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3208, दिनांक 20 अप्रैल, 2016, पत्रांक-4649, दिनांक 2 जून, 2016 एवं संकल्प सं०-7451, दिनांक 29 अगस्त, 2016
  3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-99, दिनांक 31 अक्टूबर, 2016
-

**संख्या-5/आरोप-1-22/2016 का.- 3007--** श्री मनीष कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची) के अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा-सह-कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के पद पर कार्यावधि से संबंधित कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-720/जेल, दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है ।

प्रपत्र-‘क’ में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित हैं:-

**आरोप सं०-1.** बंदी कल्याण पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन में बंदियों को मोबाईल का उपयोग पैसे लेकर कराने, मुलाकातियों से अवैध वसूली, बंदियों के साथ गाली-गलौज आदि का उल्लेख है । इस संबंध में काराधीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी ।

**आरोप सं०-2.** दिनांक 27 जुलाई, 2015 तथा दिनांक 19 अगस्त, 2015 को बंदियों द्वारा व्यवस्था एवं घटिया भोजन के लिए हड़ताल किया गया था । तीस दिनों के अंदर दो बार बंदियों द्वारा हड़ताल करना लचर कारा प्रशासन का द्योतक है । इसकी सूचना कारा निरीक्षणालय को नहीं दी गयी ।

**आरोप सं०-3.** जाँच-प्रतिवेदन के अनुसार कारा चिकित्सक द्वारा बंदियों का समुचित इलाज नहीं किया जाता है । कारा कर्मियों द्वारा बंदियों के मुलाकातियों से पैसा लिया जाता है । उन्हें खाना पहुँचाने के लिए भी पैसा लिया जाता है । यह काराधीक्षक के प्रशासनिक विफलता का द्योतक है ।

**आरोप सं०-4.** जाँच-प्रतिवेदन के अनुसार कुछ कक्षपाल रात्रि ड्यूटी में शराब पीते हैं । श्री थियोदोर सोरेंग, सहायक कारापाल स्वतंत्र रूप से कारा चलाने में अक्षम हैं । इनका नियंत्रण न तो बंदियों पर है न अधीनस्थ कारा कर्मियों पर । कारा प्रशासन की इस विफलता के लिए अधीक्षक जिम्मेवार हैं । विदित हो कि श्री सोरेंग का स्थानांतरण मंडल कारा, कोडरमा कर दिया गया है । अधीक्षक ने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि अनुभव की कमी के कारण जो त्रुटियाँ रह गई हैं, उसे वे अविलंब सुधार लेंगे । यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है ।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-3208, दिनांक 20 अप्रैल, 2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-467/जे०, दिनांक 5 मई, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । विभागीय पत्रांक-4649, दिनांक 2 जून, 2016 द्वारा कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1719/जेल, दिनांक 16 जून, 2016 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण

को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया । अतः समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-7451, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा०, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-99, दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया ।

आरोप सं०-1 पर संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि श्री तरूण बोदरा, बन्दी कल्याण पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से कोई आरोप नहीं है। जहाँ तक कक्षपाल द्वारा बंदियों के साथ गाली-गलौज करने के संबंध में भी काराधीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने का प्रश्न है तो आरोपी के बचाव-बयान में कहा गया है कि मामले के संज्ञान में आने पर उन्होंने अविलम्ब कक्षपाल श्री महादेव उराँव पर कारा के पत्रांक-857, दिनांक 29 जुलाई, 2015 द्वारा कारण पृच्छा की । तत्पश्चात् कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड को लिखित रूप से इसकी सूचना दी गयी, जिसके फलस्वरूप कक्षपाल श्री महादेव उराँव पर कार्रवाई करते हुए उसे सेवामुक्त कर दिया गया । अतः काराधीक्षक के विरुद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

आरोप सं०-2 पर संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि दिनांक 27 जुलाई, 2015 एवं दिनांक 19 अगस्त, 2015 को बंदियों द्वारा की गयी हड़ताल की सूचना नहीं दिये जाने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी के बचाव-बयान में कहा गया है कि दिनांक 27 जुलाई, 2015 एवं 19 अगस्त, 2015 को बंदियों ने कारा के अंदर की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की, जिसकी सूचना मिलते ही ये स्वयं कारा जाकर उनकी बातों को सुना तथा समस्याओं का निराकरण किया गया, जिससे बैठक तत्क्षण समाप्त कर दी गयी । कारा हस्तक के नियम-73 के आलोक में यह नित्य-प्रतिदिन की सामान्य घटना थी, अतः इसकी जानकारी कारा महानिरीक्षक को नहीं दी गयी । आरोपी के कथन के सहमत हुआ जा सकता है । अतः यह आरोप भी आधारहीन प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-3 पर संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि कारा हस्तक नियम-222 के अनुसार, जेल प्रावधान से संबंधित नियमों के अनुपालन की जिम्मेवारी कारापाल की है। आरोपी के बचाव-बयान में यह भी कहा गया है कि बन्दी की पारिश्रमिक राशि सीधे उनके खाते में Direct Beneficiary Transfer के माध्यम से जाती है । उन्हें नगद भुगतान नहीं दिया जाता है । सहायक कारापाल श्री थियोडोर सोरेंग को उनके द्वारा हमेशा निदेशित किया जाता रहा है कि किसी भी कैदी से पैसे के लेनदेन की शिकायत नहीं होनी चाहिए । आरोपी के इस कथन का अभियोजन पक्ष

द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार कारापाल की जिम्मेवारी का भार आरोपी पर डालकर इन पर आरोप गठित किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह आरोप आधारहीन है।

आरोप सं०-4 पर संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि इस आरोप के संबंध में आरोपी पदाधिकारी का कथन है कि उन्हें जब कक्षपालों द्वारा शराब पीकर झूटी करने एवं कारा में अराजकता फैलाने संबंधी सूचना सहायक कारापाल से मिली, तो उन्होंने कक्षपाल के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की। इस आरोप की प्रकृति भी आरोप सं०-3 के समान है, जिसमें यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कारापाल के जिम्मेवारी का भार आरोपी पर डालकर आरोप गठित किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह आरोप भी आधारहीन है।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री मनीष कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा-सह-कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा को उक्त सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,

सरकार के संयुक्त सचिव।

-----